SHRI EKANATH K. THAKUR:*

श्री सभापति: आप मेंबर्स के privileges के ऊपर encroachment कर रहे हैं। मेंबर्स का privilege है, question करने का, आप उनके ऊपर encroachment कर रहे हैं। मेंबर्स ने इतनी मेहनत करके questions लिखे हैं, सरकार ने उसकी तैयारी की, कितना खर्चा हुआ होगा ...(व्यवधान)... No, no. (*Interruptions*)... This matter will be discussed later. Please take your seats.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

परमाणु परीक्षणों पर रोक

161. **श्रीमती माया सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अमेरिका के बीच परमाणु परीक्षणों पर रोक संबंधी मतभेद सुलझा लिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (ग) सरकार का दृष्टिकोण यह है कि अमरीका के साथ असैनिक नाभिकीय ऊर्जा सहयोग बहाल करने के लिए 18 जुलाई का संयुक्त वक्तव्य और भारत की पृथक्करण योजना ही दिशा-निर्देशी सिद्धांत होनी चाहिए। भारत नाभिकीय परीक्षणों पर एकपक्षीय स्वैच्छिक स्थगन जारी रखने के प्रति वचनबद्ध है जैसा कि 18 जुलाई के संयुक्त वक्तव्य में दोहराया गया था।

Halting of nuclear tests

†*161. SHRIMATI MAYA SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether differences between India and USA regarding halting of nuclear tests have been resolved;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the present status thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ANAND SHARMA): (a) to (c) It is the Government's position that the guiding principle for the resumption of civilian nuclear energy cooperation with the United States must remain the framework of the 18 July Joint Statement and India's Separation Plan. India is committed to continuing

*Not recorded.

†Original notice of the question was received in Hindi.

its unilateral voluntary moratorium on nuclear testing reiterated in the 18 July Joint Statement.

श्रीमती माया सिंह: सभापति जी, मेरा पहला सप्लीमेंटरी क्वैश्चन यह है कि अमेरिकन सीनेट कमेटी में जो बिल पास हुआ है, उसमें भारत के ऊपर स्पष्ट रूप से nuclear testing के खिलाफ प्रतिबन्ध लगाया गया है, तो मैं यह जानना चाहती हूं कि यह प्रतिबन्ध सरकार मानने को तैयार है या नहीं?

श्री आनन्द शर्मा: सभापति महोदय, जैसा प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया गया है कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए सरकार के समक्ष एक ही नियम है, guiding principle है और वह है 18 जुलाई का साझा वक्तव्य। उसके अन्दर सीमाएं निर्धारित की गई हैं। साथ ही हमारी civilian nuclear facilities और strategic nuclear facilities का जो Separation Plan है, जिसे संसद में भी 11 मार्च को रखा गया, उसी की परिधि के अन्दर है। जहां तक भारत का प्रश्न है कि केवल हमने जो कहा है कि विस्फोट पर एक तरफा पाबन्दी लगाई गई थी, unilateral voluntary moratorium, we are committed only to continue with that; and that is exactly what was reiterated in the July 18th Statement and nothing beyond that.

श्रीमती माया सिंह: सर, मंत्री जी गोल-मोल घुमा कर जवाब दे रहे हैं, वे 18 जुलाई के वक्तव्य की बात कर रहे हैं। मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी क्वैश्चन यह है कि क्या यह सही है कि आपने अपने Separation Plan में साइरस रिएक्टर को 2010 तक बन्द करने का फैसला किया है, जिसकी भारत के परमाणु अस्त्र कार्यक्रम में बड़ी भूमिका है? वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान एक नया रिएक्टर बना रहा है। जब हमारे पड़ोसी देश वर्ष में 100-150 बम बनाने की क्षमता सृजित कर रहे हों, तो भारत पर ऐसी रोक लगाने का क्या औचित्य है? क्या इन दोनों देशों के बीच में जो balance है, इसके कारण वह समाप्त नहीं हो जाएगा, मंत्री जी इसे स्पष्ट करेंगे?

श्री आनन्द शर्मा: सभापति महोदय, जैसा मैंने स्पष्ट किया है कि हमारा जो समझौता होगा, वह 18 जुलाई के साझा वक्तव्य में जो उल्लेखित शर्तें है, उन्हीं के आधार पर होगा। हमारी सरकार अमेरिका और अन्य देशों के साथ केवल Civilian Nuclear Energy Cooperation की बात कर रही है। जो सामरिक कार्यक्रम हैं, strategic कार्यक्रम है, उन पर न कोई चर्चा है, न ही सामरिक कार्यक्रम को किसी भी चर्चा के अन्दर लाया गया है। जो Separation Plan है, उसे हमारे भारत के परमाणु क्षेत्र के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने तय किया है। This Separation Plan will be implemented in a phase manner. The facilities, which have been identified, have been done so by our nuclear establishment and also by those, who are overseeing India's strategic nuclear programme. We are only discussing the Civilian Nuclear Energy Cooperation. I would, once again, like to repeat myself. We are not at all discussing India's strategic nuclear programme; and the Separation Plan will be carried out in a phased

manner, so that the strategic programme is not impacted in any manner, not interrupted in any manner, and India's credible deterrent is maintained.

श्रीमती सुषमा स्वराज: धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, आपने यह उत्तर देखा होगा। यह उत्तर सरकार की ओर से बहुत दृढ़ता को प्रदर्शित करता है कि हम 18 जुलाई के वक्तव्य की चहारदीवारी से कतई इधर-उधर नहीं होंगे। आज इस उत्तर में यह जो दृढ़ता दिखाई गई है, वही दृढ़ता दो बार प्रधान मंत्री जी ने सदन में इसी विषय पर हुई चर्चाओं का उत्तर देते हुए दिखाई थी। लेकिन वास्तविकता यह है कि जिस तरह से यह समझौता आगे बढ़ रहा है, उसमें यह दृढ़ता कहीं प्रदर्शित नहीं होती। मैं आपके माध्यम से सरकार से और स्वयं प्रधान मंत्री जी यहां बैठे हैं, उनसे यह कहना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि अगर आप इतने दृढ़ हैं, तो क्या आप इस बात पर सहमत होंगे कि केवल सरकार की ओर से नहीं, बल्कि समूचे सदन की ओर से, जिसमें सत्ता पक्ष, विपक्ष, घटक दल, सभी शामिल हों और दोनों सदनों की आरे से एक ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, जिसमें देश की भावनाओं का प्रतिबिम्ब हो? दोनों सदन मिल कर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए क्या सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर सहमति देने की बात करेगी, जिसमें सारे देश की भावनाओं का प्रतिबिम्ब आ जाए और हम एक लक्ष्मण-रेखा तय कर दें कि इतना और इतने से आगे कुछ नहीं?

श्री आनन्द शर्मा: सभापति महोदय, मैं सुषमा स्वराज जी का बहुत आदर करता हूं। उन्होंने एक विचार व्यक्त किया है जिसका इस प्रश्न से, जो प्रश्न सदन के सामने है, उससे कोई सीधा संबंध नहीं है क्योंकि यह सिर्फ परमाणु विस्फोट की बात है।...(**व्यवधान**)... सुन लीजिए, भाई, मैंने भी सुना है। सभापति महोदय, जहां तक हमारी संसदीय प्रणाली की बात है, उससे आपका एक लंबा संबंध रहा है और माननीय सदस्य उस से अच्छी तरह से अवगत है। हमारी संसदीय प्रणाली के अंदर जब देश का प्रधान मंत्री देश की सरकार सदनों में स्पष्ट आश्वासन और वक्तव्य देती है, वह सर्वोपरि है। वे आश्वासन राष्ट्र हित को मद्दे नजर रखकर दिए गए। संसद को विश्वास में लेकर, दोनों सदनों के अंदर पिछली जुलाई और 11 मार्च को दिए गए। मैं यहीं कहूंगा कि सुषमा जी ने जो आशंका व्यक्त की है आने वाले समय में जैसे बात आगे बढ़ रही है...(**व्यवधान**).... अभी अमेरिका की कांग्रेस के पास यह विषय चर्चा में है। उन्होंने अपने कानून में जो संशोधन करना है, हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव्स में ....(**व्यवधान**)...

AN HON. MEMBER: You are deviating...(*interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: I am not deviating if you are trying to follow. हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स ने एक बिल पास किया है और सेनेट ने उसे पारित करना है। महोदय, अमेरिकी कांग्रेस की प्रक्रिया अलग है, हमारी संसद से अलग है।...(*Interruptions*) There both the Houses have different Bills and those Bills will be reconciled and after that only India's specific waiver will be there which will empower the President only, then can an agreement be signed. We are very clearly

stating our position that we are only for continuing a unilateral voluntary moratorium as reiterated on July 18 and not going beyond that. Here I may like to add, Sir, for the benefit of the House, to clarify any misgivings, as I had said earlier, it is only the civilian nuclear facilities which we are discussing. I would like to remind Sushmaji, with all respect, Sir, that there was a time when India's strategic restraint and doctrine was discussed when the then Prime Minister had offered in the UN General Assembly, in September 1998, to convert unilateral moratorium into a *de jure* one and the present hon. Leader of the Opposition, as the Foreign Minister ...(*Interruptions*)... Let me continue ...(*Interruptions*)...made an offer to Mr. Strobe Talbott conveying India's willingness to sign the CTBT.

श्री यशवंत सिन्हा: यह क्या है? यह क्या कह रहे है? ...(व्यवधान)... यह गलत बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)...

SHRI ANAND SHARMA: Let me complete, Sir...(*Interruptions*)... Let me complete, Sir. ...(*Interruptions*)... I have to complete, Sir. ...(*Interruptions*) ... I need your protection, Sir. ...(*Interruptions*)... I need your protection, Sir. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Honour the reply. Don't go ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, a Minister also needs protection from the Chair, ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: नहीं, हो गया। Don't invite trouble ...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, it is the right of Members to know what the factual position is ...(*Interruptions*)... Sir, I am only discharging my responsibilities. ...(*Interruptions*)... Sir, the hon. Leader of the Opposition is here. ...(*Interruptions*)... He was discussing CTBT ...(*Interruptions*)...

श्री यशवंत सिन्हा: सर, यह क्या है? सुषमा जी ने जो पूछा है, क्या उसके जवाब में यह आता है? नहीं, तो expunge कीजिए।...(व्यवधान)... उन्होंने जो बात कही है, उसे एक्सपंज कीजिए।. ..(व्यवधान)... उस दिन जसवन्त सिंह जी ने यह बात कही, वह चुप रह गए। उन्होंने कोई बात नहीं की।...(व्यवधान)... मैं कह रहा हूं कि प्रधान मंत्री डा॰ मनमोहन सिंह ...(व्यवधान)... लगातार न्यूक्लिअर टेस्ट का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने 1974 से विरोध किया...(व्यवधान)...उन्होंने 1998 में विरोध किया।...(व्यवधान)...

श्री दिग्विजय सिंह: इसे कार्यवाही से निकलवाइए।

श्री सभापति: मैं देख लूंगा। श्री सीताराम येचुरी।...(व्यवधान)...

श्री सीताराम येचुरी: सर, आप ने मुझे अनुमति दी है, इन्हें बिठाइए।I need your protection Sir. सर, आप मुझे बोलने की इजाजत दे रहे हैं।...(व्यवधान)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, I have not completed. ...(*Interruptions*)...

Sir, I have not completed. ...(*Interruptions*)...

श्री यशवंत सिन्हा: उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि प्रधान मंत्री ने बराबर न्यूक्लिअर टेस्ट का विरोध किया है। ...(व्यवधान)... यह सारा इस किताब में छपा हुआ है। ...(व्यवधान)... प्रधान मंत्री ने बराबर न्यूक्लियअर टेस्ट का विरोध किया है। ...(व्यवधान)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, this is the question which is before the House. I, as a Minister, am discharging my responsibility. ...(*Interruptions*)... I am trying to share with the august House the perspective of the UPA Government. ...(*Interruptions*)... Our approach is entirely different from that of the NDA Government ....(*Interruptions*)... Sir, I am trying to inform Members of the Opposition our negotiating strength. If this question has been put, Sir, I am only doing my duty. Thank you.

श्री दिग्विजय सिंह: सर, अगर मंत्री जी बोलेंगे तो हमें भी अनुमति दी जाए।

श्री यशवंत सिन्हा: सर, ये कुछ भी कह कर निकल जाएंगे। ...(व्यवधान)... आप उसको एक्सपंज कर दीजिए, क्योंकि वह सवाल से रिलेटेड नहीं है। ...(व्यवधान)... नहीं, तो इस पर अभी तुरन्त चर्चा हो। ...(व्यवधान)... मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है। ...(व्यवधान)... सी॰टी॰बी॰टी॰ के बारे में हमारा क्या रुख था और इनका क्या रुख है? ...(व्यवधान)...

श्री सीताराम येचुरी: सर, क्या आप हमें इस पर बोलने की इजाजत दे रहे हैं? ...(व्यवधान)...

क्या आप हमें बोलने की इजाजत दे रहे हैं, सर? ...(व्यवधान)...

श्री यशवंत सिन्हा: आप अभी इस पर चर्चा कराइए। ...(व्यवधान)...

SHRI SITARAM YECHURY: I just want to ask a question on the civilian nuclear programme itself...(*Interruptions*)... Sir, are you able to hear me? ...(*Interruptions*)...

श्री यशवंत सिन्हा: आप एकदम गलत बात बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)... आप एकदम गलत बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री दिग्विजय सिंह: अगर आप मंत्री हो, तो इसका जवाब दो। ...(व्यवधान)... इसका जवाब दो। ...(व्यवधान)...

श्री सीताराम येचुरी: एक मिनट ...(व्यवधान)... हमें इजाजत दी गई है? जरा बोलने तो दीजिए। ...(व्यवधान)... चेयरमैन साहब ने हमें इजाजत दी है, मैं उसी आधार पर बोल रहा हूं। मिनिस्टर महोदय ने जवाब देते हुए कहा कि Sir, we are discussing only the civilian nuclear programme, and we are not going into the other issues of weaponisation or strategic programme. But, on the civilian programme,

what is actually worrying all of us is that the Prime Minister has given assurances in the House, very well meaning. We all agree with those assurances. But, in spite of these assurances, we see the goal post begin shifted. On the civilian nuclear programme, we want this assurance from the Government...(*Interruptions*)... On the civilian nuclear programme, the Prime Minister, in his assurances, had assured both the Houses that whatever we do, will be contingent upon the reciprocity of what will be done in the United States of America, how they change their laws. Now, we are being asked to approach the International Atomic Energy Agency for safeguards in perpetuity, which none of the nuclear weapon countries is doing. But, we have to get into this perpetuity before the American Congress and the law-makers proceed further. Now, that is a shift in the goal post. Now, because of these shifts in the goal post, what I am asking you, Sir through you, I am requesting the Government that all that the Prime Minister has assured both the Houses, nothing beyond that, whatever he has assured both the Houses, let that, be reiterated, and let the entire House accept that as the position in this case, and we are not going beyond that ...(*Interruptions)*...We are not going a comma beyond what you have said. We are only requesting, we are urging the Prime Minister and the Government to please consider that there should be a resolution or a motion or a declaration or a sentiment, any form, but let this whole House be associated with it ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Let the Prime Minister answer ...(*Interruptions*)... Please ask the Prime Minister to reply ...(*Interruptions*)...

SHRI AMAR SINGH: Sir, I associate myself with the sentiments expressed by Sitaram Yechuryji...(*Interruptions*)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, are you permitting me to reply to Sitaram Yechuryji? Sir, the statement which we have given, is a very firm reiteration of the statements made last July in both the Houses and the statement made on the 11th of March this year. I would like to make it clear that for the Government, these statements are sacrosanct. For this Government, India's supreme national interest is the sole guiding criterion ...(*Interruptions*)... There is no departure. Coming to the specific question ...(*Interruptions*)... Sir, I have to answer a specific question. Shri Sitaram Yechury has said ...(*Interruptions*)...

SHRI SITARAM YECHURY: We are asking the Government the same thing. Whatever you want to say, please put it down in writing ...(*Interruptions*)... We are asking the same thing ...(*Interruptions*)... Whatever you have said, put it down in writing ...(*Interruptions*)... Sir, on that, I am asking them ...(*Interruptions*)... Put it down in writing. ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ...(व्यवधान)

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, let them put it down in writing. ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही 12.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Revival proposal of HDPEL

*162. SHRI TAPAN KUMAR SEN:
SHRI CHITTABRATA MAJUMDAR:

Will the Minister of SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state:

(a) the details of the revival proposal of Hooghly Dock & Port Engineering Ltd. (HDPEL);

(b) whether the same has been approved by Board for Reconstruction of Public Sector Enterprises (BRPSE);

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the action plan for improving the order book position and cash flow situation?

THE MINISTER OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI T.R. BAALU): (a) to (c) A proposal for the revival of Hooghly Dock and Port Engineers Ltd. (HDPEL), Kolkata for Rs. 381.71 crores was considered by the Board of Reconstruction of Public Sector Enterprises (BRPSE) on 8th July, 2005. The Board advised that a revised and realistic proposal duly appraised by an independent consultant should be submitted.

Accordingly M/s. IL & FS Infrastructure Development Corporation Limited (IL & FS IDC), a consultant engaged by HDPEL appraised the revised Rehabilitation-cum-Restructuring proposal which is being placed before